RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 249
दि. 09.01.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

हर व्यक्ति को न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है. मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले और हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले.

जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना. उन्होंने प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करेगी.

गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आए लोगों से कहा गया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट तुरंत बनवाया जाए और सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराए. राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाएगा.

सीएम योगी ने 'प्रारंभिक उत्तर भारत व इसके सिक्के' पुस्तक का किया विमोचन, बोले-दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र

पुस्तक 'प्रारंभिक उत्तर भारत व इसके सिक्के' का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया।

प्राचीन सिक्के भारत के प्रामाणिक इतिहास के प्रमाण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत ने हमेशा सनातन संस्कृति और इतिहास से जुड़े प्रमाणों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने कहा कि 'प्रारंभिक उत्तर भारत व इसके सिक्के' पुस्तक भारत की लोकतांत्रिक चेतना, ऐतिहासिक एकता और हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वर्षों से किए जा रहे पश्चिमी दुष्प्रचार का तथ्यात्मक उत्तर देता है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में यदि किसी को जानना है तो उसे भारत से सीखना होगा। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20

प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की

- इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए फाउंडेशन मॉडल पिलर के तहत चयनित 12 भारतीय एआई स्टार्ट-अप्स ने अपने विचार और कार्य प्रस्तुत किए
- ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य सेवा, बहुभाषी एलएलएम, सामग्री अनुसंधान, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग सिमुलेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं
- स्टार्टअप्स ने एआई क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और विशाल भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि एआई नवाचार और तैनाती का केंद्र भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है
- स्टार्टअप्स ने एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की
- स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निमार्ता हैं: प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दें
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा डेटा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित हों
- प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई मॉडलों की सफलता के लिए पूर्ण सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की।

अगले महीने भारत में आयोजित

होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए फाउंडेशन मॉडल पिलर के तहत चयनित 12 भारतीय एआई स्टार्ट-अप्स ने इस गोलमेज बैठक में भाग लिया तथा अपने विचार और कार्य प्रस्तुत किए।

ये स्टार्टअप कई विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो; ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और वैयक्तिकृत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री; इंजीनियरिंग सिमुलेशन, सामग्री अनुसंधान और विभिन्न उद्योगों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत एनालिटिक्स; स्वास्थ्य देखभाल निदान और चिकित्सा अनुसंधान आदि शामिल हैं।

एआई स्टार्टअप्स ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने एआई क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और अपार भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एआई नवाचार और तैनाती का केंद्र अब भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत अब एआई विकास के लिए एक मजबूत और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे देश वैश्विक एआई मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हो गया है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निमार्ता हैं और कहा कि देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, जो "मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" की भावना को दर्शाता हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में भी काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि विश्व स्तर पर किफायती एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल अलग होने चाहिए तथा स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

इस बैठक में अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, जीएएन, जीईएनएलओओपी, जीएनएएनआई, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सॉकेट एआई, टेक महिंद्रा और जेडईएनटीईआईक्यू सहित भारतीय एआई स्टार्टअप्स के सीईओ, प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने इस बैठक भाग लिया। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद भी इस बैठक में उपस्थित थे।

भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए, स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा मिले: प्रधानमंत्री मोदी

(जीएनएस)।

नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होने के साथ-साथ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हो।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि भारत वहनीय एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' से पहले, भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यमी देश के भविष्य के सह-निमार्ता हैं।

अगले महीने आयोजित होने वाले 'एआई फॉर ऑलः ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज' शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके 12 भारतीय एआई स्टार्टअप ने बैठक में भाग लिया तथा अपने विचारों और कार्य से अवगत कराया।

बाद में, 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि उन्होंने भारतीय स्टार्टअप जगत के युवाओं के साथ एआई पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "यह एक यादगार और ज्ञानवर्धक बातचीत थी, जिसमें उन्होंने एआई की दुनिया में भारत के परिवर्तन के बारे में अपना दृष्टिकोण और कार्य साझा किया। यह प्रशंसनीय है कि ये स्टार्टअप ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग सिमुलेशन, सामग्री अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अनुसंधान जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि एआई का उपयोग समाज कल्याण के लिए कैसे किया जा सकता है।

बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआई का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निमार्ता हैं। उन्होंने कहा कि देश में नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है।

स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने इंडसफूड 2026 में भाग लिया, जिसके दौरान इसने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारती स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य निर्यात के लिए तैयार स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच और नीतिगत सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है।

इस चैलेंज से चयनित स्टार्टअप्स को दुबई में गल्फूड और जर्मनी में बायोफेच में भाग लेने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे वे वैश्विक बाजार में अवसरों का पता लगा कर भारत के कृषि-निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकेंगे।

झारखंड के लिए गौरव का पल, यूथ आइकॉन आर्यन गर्ग प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे सीधा संवाद

लातेहार। झारखंड राज्य के युवा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यूथ आइकॉन आर्यन गर्ग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करेंगे। यह ऐतिहासिक संवाद कार्यक्रम 09 से 12 जनवरी 2026 के दौरान भारत मण्डपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। जिसमें देशभर से चयनित युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, नवाचारकर्ता एवं नीति-निमार्ता भाग ले रहे हैं। इस मंच पर झारखंड से प्रतिनिधित्व करते हुए आर्यन गर्ग की उपस्थिति राज्य के युवाओं के लिए गर्व का विषय है। संवाद के प्रमुख विषय : विकसित भारत 2047,युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका,शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक नवाचार,ग्रामीण विकास एवं युवा सशक्तिकरण, नेतृत्व और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी।

आर्यन गर्ग शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे हैं।

वायु सेना अध्यक्ष ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया

वायु सेना अध्यक्ष ने कैडेटों से एनसीसी के मूल्यों को कायम रखने और सदैव राष्ट्र की सेवा करने का आ'ान किया

(जीएनएस)।

वायु सेना अध्यक्ष (सीएएस) एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 8 जनवरी, 2026 को दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) का दौरा किया।

एयर चीफ मार्शल ने सेना, नौसेना और वायु सेना के एनसीसी कैडेटों के 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया। उसके बाद राजस्थान के पिलानी स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं ने बैंड प्रदर्शन किया। वायु सेना अध्यक्ष ने विभिन्न सामाजिक जागरूकता विषयों पर एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों के कैडेटों द्वारा तैयार 'फ्लैग एरिया' का निरीक्षण किया और एनसीसी 'हॉल

ऑफ फेम' का भी दौरा किया।

वायु सेना अध्यक्ष ने कैडेटों को संबोधित करते हुए देश के युवाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया और राष्ट्र निर्माण तथा अनुशासित, देशभक्त और मूल्यों से प्रेरित नागरिकों को तैयार करने में एनसीसी की भूमिका की सराहना की। वायु सेना अध्यक्ष ने देशभर में एनसीसी की व्यापक उपस्थिति की चर्चा की, जिससे यह 20 लाख से अधिक कैडेटों और 40 प्रतिशत छात्राओं से युक्त विश्व का सबसे बड़ा वदीर्धारी संगठन बन गया है। वायु सेना अध्यक्ष एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और विभिन्न सरकारी पहलों को बढ़ावा देने में एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कैडेटों से राष्ट्रवाद को कायम रखने और जीवन में कभी हार न मानने वाले रवैये के साथ निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत रहने को कहा।

वायु सेना अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आरडीसी 2026 में अपने-अपने निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैडेटों को बधाई दी।

एनसीसी कैडेटों ने समूह गीत, बैले और समूह नृत्य प्रदर्शनों के द्वारा देश की समृद्ध और विविध संस्कृति प्रदर्शित करते हुए मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी एयर चीफ मार्शल और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने सराहना की।

विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड की 14वीं 'हिंदी सलाहकार समिति' की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई

केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के महत्व पर जोर दिया

(जीएनएस)।

विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड की 14वीं "हिंदी सलाहकार समिति" की पहली बैठक आज यहां केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्‍ वतंत्र प्रभार), श्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्‍ ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई । इस अवसर पर राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के विषय पर चर्चा हुई ।

केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के राजभाषा खंड की पहल और प्रयासों पर संतोष व्‍ यक्‍ त किया । उन्होंने विधि के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड की सराहना की । बैठक के दौरान, राजभाषा अर्थात विधि के क्षेत्र में हिंदी, के प्रचार और प्रसार को सुनिश्चित कए जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा की उपयोगिता को आम आदमी के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जिसमें "कार्य करने में सुगमता", "शब्दों और अभिव्यक्तियों के प्रयोग की सरलता", और "विचारों तथा कार्यों को अस्पष्टता से परे, सही भावना के अनुरूप व्यक्त करना' शामिल है ।

एसईसीएल ने स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए श्री सत्य साई ट्रस्ट के साथ साझेदारी की

एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ में 35.04 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए श्री सत्य साई ट्रस्ट के साथ साझेदारी की

नव रायपुर में अत्याधुनिक संस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के युवाओं को निःशुल्क, रोजगारोन्मुखी स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण प्रदान करेगा

(जीएनएस)।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

हैं। इस परियोजना के लिए 35.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कोयला क्षेत्र के युवाओं के लिए निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

यह प्रस्तावित संस्थान सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को नर्सिंग सहायक, तकनीशियन और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों सहित प्रमुख स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना है।

इसके परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं और संबद्ध अवसंरचना शामिल होगी। एसईसीएल के परिचालन जिलों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन जिलों के लिए वार्षिक प्रवेश का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा 25 वर्षों की अवधि के लिए आरक्षित रहेगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

पहले सीईओ सम्मेलन का आयोजन किया

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें आईआईसीडीईएम 2026 की बारीकियों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी ।

सीईओ ने संबोधन के बाद उन 36 विषयगत समूहों पर चर्चा की, जिनका नेतृत्व संबंधित सीईओ आईआईसीडीईएम 2026 में करेंगे ।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 9 जनवरी को 100 रेलवे अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रेल मंडलों को 26 शील्ड प्रदान करेंगे

(जीएनएस)।

भारतीय रेल, संगठन में अपनी बेहतरीन सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए 100 कर्मठ कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिष्ठित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने जा रहा है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि), द्वारका, नई दिल्ली में किया जाएगा।

रेलवे, सूचना और प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, चयनित रेलवे कर्मचारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस समारोह में रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री वी. सोमन्ना, रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सतीश कुमार, साथ ही रेलवे बोर्ड के सदस्य और विभिन्न रेल मंडलों और प्रोडक्शन यूनिट के माह प्रबंधक शामिल होंगे।

अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 के लिए नवाचार, संचालन दक्षता, सुरक्षा, संरक्षा, राजस्व वृद्धि, परियोजना को समय पर पूरा करने, खेल में बेहतरीन प्रदर्शन और सेवा के अन्य खास क्षेत्रों में योगदान करने वाले 100 लोगों का चयन किया गया है।

नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना

17 अधिकारियों और कर्मचारियों

को नवाचार, प्रक्रिया शुरू करने के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिससे उत्पादकता में सुधार होगा, खर्च में कमी आएगी, आयात कम होगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे में दक्षता में वृद्धि होगी।

बहादुरी और निस्वार्थ सेवा का सम्मान

22 रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना किए गए निःस्वार्थ और सराहनीय सेवा व सुरक्षा कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और रेलवे संपत्ति की रक्षा हुई, और सार्वजनिक सेवा के प्रति असाधारण साहस, प्रतिबद्धता और समर्पण का उदाहरण पेश किया गया।

राजस्व वृद्धि और सतर्कता

14 अधिकारियों और कर्मचारियों को रेलवे की आय में वृद्धि करने और बिना टिकट यात्रा, चोरी और अन्य कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिससे वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

परिचालन उत्कृष्टता और संपत्ति संरक्षण

19 कर्मचारियों और अधिकारियों को परिचालन में सुधार, सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने, बेहतर रखरखाव प्रथाओं को सुनिश्चित करने और रेलवे संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा।

बड़ी परियोजना का समय पर पूरा होना

16 अधिकारियों और कर्मचारियों को रिकॉर्ड समय में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे को विस्तार देने, क्षमता बढ़ाने और बेहतर संचालन प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

10 अधिकारियों और कर्मचारियों को परिभाषित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा, जो भारतीय रेलवे के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में पेशेवर उत्कृष्टता, समर्पण और प्रभावशाली योगदान को दशार्ता है।

बेहतरीन खेल प्रदर्शन का भी सम्मान : रेलवे अपने 2 खिलाड़ियों को भी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 से सम्मानित करेगा, जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है और भारतीय रेलवे का नाम रोशन किया है।

व्यक्तिगत सम्मान से परे : व्यक्तिगत सम्मान के अलावा, अलग-अलग श्रेणियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रेल मंडलों को 26 शील्ड प्रदान किए जाएंगे, जो उनकी शानदार उपलब्धियों और कुल मिलाकर बेहतरीन प्रदर्शन को पहचान देंगे।

सम्मानित होने वालों में ऐसे रेल कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षित और बिना किसी व्यवधान के रेलवे संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेल कर्मियों के विशेष योगदान को भी सम्मान मिलेगा जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी रेलवे संचालन और जनता को राहत सुनिश्चित की। साथ ही ऐसे कर्मी भी सम्मानित सोची में हैं जिन्होंने मुश्किल सेक्शन में एडवांस्ड बैलास्ट क्लीनिंग मशीनों को पेश किया, जिससे ट्रैक सुरक्षा, यात्रा की गुणवत्ता और लंबे समय तक रखरखाव की दक्षता में काफी सुधार हुआ।

यह पुरस्कार समारोह भारतीय रेलवे के समर्पण, उच्च व्यावसायिकता और अनुकरणीय सेवा को पहचानने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, साथ ही एक सुरक्षित, अधिक कुशल और यात्री-केंद्रित रेल प्रणाली बनाने में अपने कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का उत्सव भी मनाता है।

पीलीभीत में DIG/SP ने सुनीं जनशिकायतें, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत।जनशिकायतों के शीघ्र एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हेतु उ‌क्क्ष्ट्ठरढ पीलीभीत द्वारा पुलिस कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजन की शिकायतें सुनी गईं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए।

आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उ‌क्क्ष्ट्ठरढ ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए। जिला प्रशासन इस तरह की जनसुनवाई को नियमित रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जनता को न्याय मिल सके।

इस पहल से स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। संबंधित थानों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का एक निश्चित समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए।

पीलीभीत:डीजीपी/एसपी के निर्देशन में मिशन शक्ति-5 का सफल आयोजन

ब्यूरो रिपोर्ट:

पीलीभीत के उ‌क्क्ष्ट्ठरढ के निर्देशन में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत थाना हजारा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया।

इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिसमें पुलिस टीम ने ग्रामीणों के बीच जाकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की

जागरूकता गतिविधियाँपुलिस टीम ने बालिकाओं और महिलाओं को महिला अपराधों जैसे छेड़छाड़, घरेलू हिंसा आदि से बचाव के उपाय बताए।साइबर अपराधों पर विशेष जोर देते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया जोखिमों और सतर्क रहने की सलाह दी गई।

हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112 और महिला हेल्पडेस्क की जानकारी प्रदान कर तत्काल सहायता लेने का आ'ान किया।

अभियान का महत्वमिशन शक्ति-5 उत्तर प्रदेश सरकार की नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की महत्वाकांक्षी योजना है, जो विभिन्न थानों में सक्रिय रूप से चल रही है।

पीलीभीत पुलिस द्वारा नियमित भ्रमण और चौपालों के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी।

यह प्रयास नवरात्रि और अन्य अवसरों पर और गति पकड़ लेता है।

पीलीभीत सांसद ने केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी से स्थानीय राजमार्ग परियोजनाओं पर की विस्तृत चर्चा

(जीएनएस)।

पीलीभीत के सांसद ने नई दिल्ली, 8 जनवरी 2026: को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के विकास के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर गहन चर्चा हुई। सांसद ने क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने हेतु कई लंबित प्रस्तावों को तेजी से पूरा करने का अनुरोध किया।

भेंट के दौरान सांसद ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर आसाम रोड से पीलीभीत-खटीमा खंड के चार लेन निर्माण एवं चौड़ीकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना पीलीभीत को उत्तराखंड के खटीमा से बेहतर तरीके से जोड़ेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। इसी क्रम में बरेली-बीसलपुर तथा बीसलपुर-शाहजहाँपुर सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया। इन सड़कों के विस्तार से क्षेत्रीय यातायात सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी।

सांसद ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

पर भी ध्यान दिलाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर खुटार से पीलीभीत मार्ग के ग्राम कढ़ेरचौरा क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु डिवाइडर निर्माण का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां वाहनों के आपस में टकराव से कई जानें जा चुकी हैं। डिवाइडर बनने से सड़क सुरक्षा में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े सभी लंबित एवं प्रस्तावित कार्यों पर मंत्री महोदय के साथ विस्तृत समीक्षा की गई।

श्री नितिन गडकरी ने सांसद के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि पीलीभीत जिले की सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार हो। सांसद ने इस भेंट को क्षेत्रवासियों के लिए सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि सड़क विकास से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पीलीभीत जिला, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है, सड़क दुर्घटनाओं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से लंबे समय से जूझ रहा है। सांसद की यह पहल स्थानीय निवासियों के लिए राहत की उम्मीद जगाती है। संबंधित विभागों से उम्मीद है कि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई होगी।

पत्रकार विवेक अस्थाना के परिवार को सीएम योगी ने दिया आर्थिक संबल, हृदयघात से हो गया था निधन

गोरखपुर (जीएनएस)। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के आजीवन सदस्य, पत्रकार, रंगकर्मी विवेक अस्थाना का पांच जनवरी को हृदयाघात से निधन हो गया था। वह परिवार के एकमात्र आयार्जक सदस्य थे। परिवार की सहायता के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की तरफ से, बुधवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया था। सीएम योगी ने त्वरित संवेदना दिखाई और 19 घंटे के भीतर परिवार को आर्थिक सहायता मिल गई।

हर जरूरतमंद के साथ आत्मिक संवेदना रखते हुए भरपूर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह दिवंगत पत्रकार विवेक अस्थाना के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अस्थाना की पत्नी और दोनों बच्चों को विवेकाधीन कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा और उन्हें आश्वस्त किया कि दुःख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ हैं।

गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के आजीवन सदस्य, पत्रकार, रंगकर्मी विवेक अस्थाना का पांच जनवरी को हृदयाघात से निधन हो गया था। वह परिवार के एकमात्र आयार्जक सदस्य थे। परिवार की सहायता के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब की तरफ से, बुधवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया

था। सीएम योगी ने त्वरित संवेदना दिखाई और 19 घंटे के भीतर परिवार को आर्थिक सहायता मिल गई।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह विवेक अस्थाना की पत्नी निहारिका, दोनों बच्चों दिव्य और देव से गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में मुलाकात की। उनका दुःख बांटा। पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

सीएम ने परिवार को यह भी भरोसा दिया कि उनकी हर संभव

पटना : हाड़कंपाने वाली सर्दी के बीच बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां

पटना, (जीएनएस)। इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, बिहार की राजधानी में पटना में भी हालात काफी खराब हैं, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 5 दिन तक यहां पर अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रहने का पूवार्नुमान है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार से कोहरे की स्थिति और खराब हो सकती है इसी के मद्देनजर पटना में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।पटना ऊ्ट के नए आदेश के तहत पटना में क्लास 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे।

9वीं क्लास और उससे ऊपर की क्लास सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चल सकती हैं। प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाओं के लिए होने वाली स्पेशल क्लास/परीक्षाओं को इससे छूट दी जाएगी।

न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण दृश्यता भी कम है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी 2026 को यहां पर उङ्क'हिं्1 स्थिति रहेगी। सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जिससे विजिबिलिटी कम रह सकती है।

रात के समय सर्दी और बढ़ने के आसार

दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन धूप तेज नहीं होगी। ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है, वहीं रात के समय सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना कम है।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पटना जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के साथ-साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को भी निर्देश दिया है कि वे आदेश का पालन करें। यदि मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आगे भी छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है।

दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर,के थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में 19 वर्षीय आरोपी मुजीब को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आईफोन-13 मोबाइल भी बरामद कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के सख्त निदेर्शों पर की गई।

घटना का विवरण7 जनवरी 2026 को एक ग्रामीण ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उनकी 11-12 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी पड़ोस का चाचा था, जिसने बच्ची को

लालच देकर घर बुलाया और क्रूरता से दुराचार किया। वीडियो वायरल होने पर परिजनों को घटना का पता चला।

कानूनी कार्रवाई तहरीर पर आरोपी मुजीब के खिलाफ धारा 65(2), 351(2), 127(2) बीएनएस, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट और 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 8 जनवरी 2026 को मुखबिर सूचना पर गढ़वाखेड़ा बैंक के पास से आरोपी को दबोचा गया। आरोपी फरार चल रहा था और धमकी देकर बच्ची को चुप रखता था।

पुलिस टीम और आगे की कार्यवाहीपुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, हेड कॉन्स्टेबल अनूप मिश्रा और कॉन्स्टेबल शोभित कुमार शामिल थे। आरोपी को कोर्ट भेज दिया गया है, जबकि विवेचना जारी है और साक्ष्य संकलन तेजी से हो रहा है ताकि दोषी को कड़ी सजा मिले। थाना प्रभारी ने पुष्टि की कि आरोपी जेल में है।

कस्बा बड़ागांव स्तिथ रामलीला मैदान में चल रही श्री रामलीला (धनुष यज्ञ)

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी । कस्बा बड़ागांव स्तिथ रामलीला मैदान में चल रही श्री रामलीला(धनुष यज्ञ) के दूसरे दिन जय श्री राधा कृष्ण रामलीला नाट्य कला मंदिर दरभंगा बिहार (समस्तीपुर)से आए कलाकारों द्वारा फुलवारी लीला व नगर दर्शन का मंचन किया गया।

लखन हृदय लालसा विशेषी जय जनकपुर आवे देखी ।

मंचन में लक्ष्मण जी के हृदय में

लालसा होती है कि मैं जनकपुर जाकर देखो तो वह राम जी को इशारों में कहते है। तब भगवान श्री राम ग्रुप विश्वामित्र से आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर देखने के लिए चल देते हैं। दोनों भाई जैसे ही जनकपुर में प्रवेश करते हैं ।तो वहां के नर नारी दोनों भाइयों को देखकर खिड़कियों के झरोखे से पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं । ऐसे सुंदर बालकों को देखकर जनकपुर के लोग खुशी से नहीं समा रहे हैं जब राम लक्ष्मण जनकपुर की बाजार पहुंचते हैं तो वहां के दुकान लगाए लोगों को इच्छा होती है । कि भगवान श्री राम हमारी दुकान से कुछ ना कुछ खरीद ले जिससे मैं धन्य हो जाऊं। बाजार से वापसी के दौरान भगवान श्री राम पूजा के लिए जब फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर जनक नंदिनी सीता गौरी पूजा के लिए फूल तोड़ रही होती है । सीता जी को देखकर मुग्ध हो जाते हैं वही सीता जो भी भगवान को देखकर मोहित हो जाती है। बात विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर सीता स्वयंवर मिलने जाते हैं। इस मौके पर मास्टर सुरजन सिंह उपाध्यक्ष रामू वर्मा,राजु जयसवाल, कोषाध्यक्ष कल्लू राम यादव, सचिव विजय वर्मा, विशेष सलाहकार राम सरन जयसवाल,बब्लू वर्मा,सुरज यादव, राजेन्द्र यादव, रितेश यादव,लल्लु यादव, कमलेश यादव, मनमोहन सेनी, श्यामाचरण गुप्ता,सुबोध श्रीवास्तव, पुजारी वर्मा, अवधराम गुप्ता,शुभम वर्मा,आदि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे ।

अनुसूचित जनजाति खिलाड़ियों के लिए 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' में भाग लेने का अवसर

11 जनवरी तक करा सकेंगे पंजीकरण

पीलीभीत। उप निदेशक खेल, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निदेर्शों के अनुपालन में 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' का आयोजन छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल सात खेलों — फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी (अर्चरी), एथलेटिक्स, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती की स्पधाएं पुरुष एवं महिला वर्ग में आयोजित की जाएंगी।उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में केवल अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरुष खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इच्छुक खिलाड़ी अपना पंजीकरण 11 जनवरी, 2026 तक जिला खेल कार्यालय, गांधी स्टेडियम, पीलीभीत में कराना सुनिश्चित करें।पंजीकरण के समय खिलाड़ियों को अपना आधार कार्ड एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यता अभियान को लेकर फतेहपुर मे बैठक का आयोजन

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यता अभियान को लेकर गुरुवार को महादेव तालाब फतेहपुर मे बैठक का आयोजन किया गया बैठक मे जिला प्रभारी छोटा योगी मोहित हिंदु ने कार्यकताओं को सदस्यता ग्रहण कराते हुए हिंदु रक्षा की शपथ दिलाई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए छोटा योगी मोहित हिंदु ने कहा कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या के महान परम पूज्य राजू दास जी महाराज जी के निदेर्शानुसार जनपद बाराबंकी मे कार्यकारिणी गठन का कार्य किया जा रहा है मोहित हिंदु ने कहा कि

प्रत्येक सप्ताह में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाए और गांव-गांव जाकर लोगों को संगठन में जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अपील की

उन्होंने कहा कि हिंदू एक है तो सेट है हिंदू बटेगा तो कटेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बांग्लादेश है जाति पात की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई है।

इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष शुभम कसौधन जिला उपाध्यक्ष पवन विश्वकर्मा जिला महामंत्री करण सिंह जिला उपाध्यक्ष मनोज सैनी विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी आशीष कुमार विश्वकर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

नये साल में एक बार फिर विधानसभा चुनावों का दौर होगा शुरू

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल के चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनावी विजय के रथ पर सवार है जिसके कारण विपक्ष और क्षेत्रीय दल बचाव की मुद्रा में हैं। भाजपा चुनाव दर चुनाव विपक्ष के गढ़ में सेंध लगा रही है। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर से सत्ता के लिये राजनीतिक दलों में संग्राम देखने को मिलेगा। कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है तो कहीं पटखनी देने की कवायद देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पाटा अब तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में भाजपा तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में बने रहने तैयारी में है। 2025 का पूरा साल राजनीतिक उठापटक से भरा रहा। शुरूआत में दिल्ली में चुनाव हुए तो अंत बिहार के विधानसभा चुनाव से हुआ। दिल्ली और बिहार दोनों जगह भाजपा ने अपनी सत्ता कायम की। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी और बिहार में भाजपा के सहयोगी नीतीश वुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह साल भाजपा के लिए चुनावी तौर पर बेहद सफल रहा। उसने न सिर्प अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि सहयोगी दलों का साथ निभाने और सटीक राजनीतिक धारणा तय करने की अपनी क्षमता भी दिखाईं। भाजपा यह संदेश देने में सफल रही कि नरेन्द्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी अब भी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली जोड़ी है। अब नये साल में एक बार फिर विधानसभा चुनावों का दौर शुरू होने पर सियासी हलचल तेज होने वाला है। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 साल से ममता बनजा मुख्यमंत्री हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस फिर जीतती है तो ममता बनजा लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और ऐसा करने वाली वे देश की पहली मुख्यमंत्री होंगी। अब तक यह रिकॉर्ड तमिलनाडु की जयललिता के नाम है जो 5 बार मुख्यमंत्री बनीं लेकिन उनके कार्यकाल लगातार नहीं थे। ममता बनजा चुनाव से पहले भाजपा के आामक तेवर से दबाब में दिख रही हैं। खुद तृणमूल कांग्रेस पूट पड रही हैं, वरिष्ठ नेता हुमायूं कबीर के नईं पाटा बना ली है। कबीर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर तृणमूल कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालिया मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज कर दी है। इस बार भी चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधी लड़ाईं है। कांग्रेस और वामदल खोये हुये जनाधार को फिर हासिल करने की कोशिशों में लगे हैं। वेंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से पश्चिम बंगाल की मां, माटी और मानुष तीनों को खतरा है। शाह ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनजा को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनजा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तैनाती का हवाला देकर इसे रोक पाने में विफलता के लिए गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रही हैं जबकि शाह ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल से घुसपैठिए चुन चुन कर निकाले जाएंगे। असम में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। इस बार भाजपा ने 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ हर चुनाव में जाति, क्षेत्र और समुदाय का अहम भूमिका रहती है। तीसरी बार सत्ता में आने से भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने आठ परटियों के साथ गठबंधन किया है। अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और विपक्ष के मंसूबों पर पानी पेरने के लिये वह साम दाम दंड भेद करी नीति पर अमल कर रहें हैं। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां पिछले 60 साल से कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनी। यहां की राजनीति पर द्रमुक और अन्नाद्रमुक का दबदबा रहा है। इस बार भाजपा अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं सुपरस्टार विजय की पाटा टीवीके भी चुनावी मैदान में पहले से ही ताल ठोंक रही है जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

यहां की राजनीति में काफी गहमागहमी होती है। हर चुनाव में फिल्मी सितारे, क्षेत्रीय दलों की ताकत और गठबंधन सभी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। केरल में वामदलों की सरकार है। यहां लंबे समय से सत्ता बदलने की परंपरा रही है लेकिन 2021 में वाम मोर्चा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर नया इतिहास रचा था। कांग्रेस गठबंधन इस बार शासन के विफल होने का दावा कर रही है और इसको मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। भाजपा अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है हालांकि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट और दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव जीतकर सनसनी पैला दी थी। पुडुचेरी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार बनी और एन. रंगासामी मुख्यमंत्री बने। यह पहला मौका था जब भाजपा सीधे तौर पर पुडुचेरी में सत्ता का हिस्सा बनी। इस बार कांग्रेस द्रमुक के साथ गठबंधन कर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा कराये जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एसआईआर की प्रीया से फजा मतदाताओं की पहचान तेजी से हो रही है और एक एक करके हर राज्य में जिस तरह से नये तथ्य सामने आ रहे हैं उससे मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले विपक्षी दलों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनावी विजय के रथ पर सवार है जिसके कारण विपक्ष और क्षेत्रीय दल बचाव की मुद्रा में हैं। भाजपा चुनाव दर चुनाव विपक्ष के गढ में सेंध लगा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में भाजपा को मिली एकतरफा जीत ने

दाल-तेल-दूध के साथ रसोई में क्या-क्या महंगा होगा? जेब पर कितना डाका?

(जीएनएस)।

केंद्रीय बजट 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश करेंगी। पिछले साल के बजट में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आयकर में राहत और जीएसटी दरों में बदलाव किए गए थे, लेकिन 2026 में फोकस राजकोषीय मजबूती, रक्षा, एमएसएमई और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा।

लेकिन बड़ा सवाल महंगाई का है - एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 में फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट राइज करेगा, जिससे रसोई के आइटम्स जैसे दाल, तेल, दूध और सब्जियां महंगी हो सकती हैं। रुपये की कमजोरी, आयात निर्भरता और वैश्विक अनिश्चितताओं से दबाव बढ़ेगा। 2025 बजट में इन्फ्लेशन कंट्रोल पर फोकस था, लेकिन 2026 में कैपेक्स बढ़ाने से मांग बढ़ सकती है, जो प्राइस हाइक का कारण बनेगी। आइए, इस रिपोर्ट में महंगाई की लिस्ट, 2025 ५२ 2026 बजट की तुलना और डीप एक्सप्लेनर (टाइमलाइन, चार्ट, इमेजेस) के साथ विस्तार से समझते हैं....

बजट 2026 की उम्मीदें- ग्रोथ कंटिन्यू लेकिन महंगाई का खतरा

बजट 2026 में सरकार की प्राथमिकताएं राजकोषीय अनुशासन, सेक्टर-लेड इन्वेस्टमेंट और टैक्स सर्टेनिटी पर होंगी। डेलॉइट और ए जैसी एजेंसियों के अनुसार, कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) बढ़ेगा, जो इन्फ्रा और एमएसएमई को बूस्ट देगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट महंगाई हो सकता है। रुपये का अवमूल्यन (डॉलर के मुकाबले कमजोरी) आयातित सामानों जैसे खाद्य तेल और दालों को महंगा करेगा। क्ऊफ्छ का अनुमान है कि सीमेंट जैसे आइटम्स 6-7% महंगे होंगे, जो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग को प्रभावित करेगा।

2025 बजट में इन्फ्लेशन 1.61% से 2.07% तक रहा, जो रिकॉर्ड लो था। लेकिन 2026 में फूड इन्फ्लेशन 2-4% तक बढ़ सकता है, क्योंकि डिफ्लेशन (महंगाई में कमी) का दौर खत्म हो रहा है। क्रिसिल के डीके जोशी कहते हैं कि GST कट्स, लो फूड इन्फ्लेशन और IT राहत से घरेलू खपत बढ़ेगी, लेकिन ग्लोबल स्टॉर्म्स (भू-राजनीतिक तनाव) महंगाई बढ़ाएंगे। लेमन मार्केट्स के गौरव गर्ग का कहना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट बजट का बड़ा हिस्सा है, जो ग्रोथ को रोक रहा है।

क्या-क्या महंगा हो सकता है?

2026 में वैश्विक अनिश्चितताएं, रुपये की कमजोरी और बजट में कैपेक्स बढ़ाने से मांग बढ़ेगी, जो प्राइस हाइक का कारण बनेगी। फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट राइज करेगा, जिससे रसोई बजट पर असर पड़ेगा। यहां मुख्य आइटम्स की लिस्ट और वजहें:

दालें: 10-15% महंगी। आयात निर्भरता (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से) और रुपये की कमजोरी से दाम बढ़ेंगे। 2025 में डिफ्लेशन था, लेकिन 2026 में मांग बढ़ने से प्राइस हाइक।

खाद्य तेल (एडिबल ऑयल): 8-12% बढ़ोतरी। इंडोनेशिया, मलेशिया से आयात, ग्लोबल प्राइस बढ़ने से असर। 2025 में ऑयल प्राइस 132% बढ़े थे, 2026 में भी ट्रेंड जारी।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स: 5-8% महंगे। फीड कॉस्ट (चारा) बढ़ने से। क्ऊफ्छ के अनुसार, फूड इन्फ्लेशन 2026 में 6-7% तक, जिसमें डेयरी बड़ा रोल।

सब्जियां और फल: 15-20% तक। मौसम अनिश्चितता और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से। टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां पहले से महंगी, 2026 में और दबाव।

चावल और गेहूं: 4-6% बढ़ोतरी। मांग बढ़ने और एक्सपोर्ट पॉलिसी से। राइस इन्फ्लेशन 2025 में बढ़ा था, 2026 में जारी।

चीनी और मसाले: 5-10%। ग्लोबल कमोडिटी प्राइस से असर। चीनी पर GST कट्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी।

अन्य: आटा, नमक, चाय-कॉफी 3-5% महंगे। इंपोर्टेड सामान पर रुपये की कमजोरी से।

सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रसेन्स के सीईओ संजय कुमार कहते हैं कि मुद्रा कमजोरी और कम FDI से दाल-तेल 2026 में महंगे रहेंगे। कुमार का अनुमानः फूड इन्फ्लेशन 60-70% कॉस्ट पर असर डालेगा।

: कितना अलग? तुलना और प्रभाव

2025 बजट में फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल, टैक्स राहत और उपभोग बूस्ट पर था। 2026 में ग्रोथ कंटिन्यू लेकिन फिस्कल डेफिसिट 4.4% से कम करने पर जोर। यहां मुख्य डिफरेंस:-

2025: GDP ग्रोथ 6.4%, इन्फ्लेशन लो (1.61%), कैपेक्स 1.5 लाख करोड़ राज्यों को, नई टैक्स स्कीम (12 लाख तक जीरो टैक्स)।

2026: GDP ग्रोथ 7.4%, इन्फ्लेशन राइज (2-4%), कैपेक्स बढ़ा (रेलवे 2.65 लाख करोड़), टैक्स रिफॉर्म्स लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं। फोकस डिफेंस, ग्रीन एनर्जी।

2025 में फूड डिफ्लेशन था, 2026 में राइज। रेलवे ने 2025-26 बजट का 80% इस्तेमाल कर लिया, 2026 में और बढ़ोतरी। ICRA के अनुसार, सीमेंट डिमांड 6-7% बढ़ेगी, जो कंस्ट्रक्शन महंगा करेगी। ए इंडिया: टैक्स सर्टेनिटी और सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर फोकस।

फरवरी 2025: बजट 2025 पेश - टैक्स राहत, कैपेक्स 1.5 लाख करोड़, इन्फ्लेशन कंट्रोल।

अगस्त 2025: CPI इन्फ्लेशन 2.07%, किचन आइटम्स महंगे (ऑयल 132%)।

अक्टूबर 2025: फूड इन्फ्लेशन लो (0.25%), लेकिन 2026 में राइज की चेतावनी।

दिसंबर 2025: GDP ग्रोथ 7.4% अनुमान, फूड डिफ्लेशन खत्म।

जनवरी 2026: बजट 2026 एक्सपेक्टेशंस - कैपेक्स बढ़ा, इन्फ्लेशन 2-4%।

फरवरी 2026: बजट पेश - महंगाई पर फोकस?

इन्फ्लेशन चार्टः किचन आइटम्स का ट्रेंड

यह चार्ट दिखाता है कि 2025 में फूड इन्फ्लेशन लो रहा, लेकिन 2026 में राइज अनुमानित। दाल-तेल जैसे आइटम्स पर असर।

महंगाई से निपटने के टिप्स और सरकार की चुनौतियां

बजट 2026 में महंगाई कंट्रोल के लिए GST रेशनलाइजेशन और एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स से रिस्क रहेगा। घरेलू स्तर पर लोकल प्रोडक्ट्स यूज करें, बल्क बाइंग से बचत। 2025 से अलग, 2026 में फोकस ग्रोथ पर, लेकिन इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग जरूरी। सरकार को टरटए और कृषि पर निवेश बढ़ाना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी, तो मिडल क्लास पर बोझ। हमारा अनुमान - 2026 में रसोई बजट 10-15% बढ़ सकता है।

ईडी रेड रोकने हाई कोर्ट पहुंची आई-पैक, ममता के पहुंचते ही पलटा खेल? कोलकाता ड्रामे की इनसाइड टाइमलाइन

ED Raid I-PAC TimeLine: कोलकाता में 08 जनवरी को जो हुआ, उसने बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी, फिर अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मौके पर पहुंचना और अब I-PAC VS का कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। पूरा घटनाक्रम किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं रहा। ऐसे में आइए जानें पूरी टाइमलाइन।

ED और I-PAC दोनों पहुंची हाई कोर्ट

ईडी के छापेमारी के खिलाफ अब IPAC भी हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसने तुरंत रेड रोकने की मांग की है। दूसरी ओर ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसकी जांच में दखल दिया गया।

एजेंसी का कहना है कि जब वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में वैध तरीके से तलाशी ले रही थी, उसी दौरान कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने दस्तावेजों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। ईडी ने अदालत से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार (09 जनवरी) को जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच के सामने होने की संभावना है।

किस मामले में हुई छापेमारी?

ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दल या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं की गई। एजेंसी का दावा है कि छापे अवैध कोयला तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत किए गए।

08 जनवरी को कुल 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई, जिनमें 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में बताए जा रहे हैं। इनमें क-ढअउ का कोलकाता स्थित कार्यालय और उसके सह संस्थापक व डायरेक्टर प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था।

छापेमारी को लेकर क्या कह रही है ईडी?

ईडी ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी कार्यालय पर छापा नहीं मारा गया। जांच उन परिसरों तक सीमित है, जहां कैश जनरेशन और हवाला ट्रांसफर से जुड़े इनपुट मिले थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि तलाशी के दौरान कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर जांच में अवैध दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए, जो कानून का सीधा उल्लंघन है।

सुबह से शाम तक कैसे बदला माहौल

8 जनवरी की सुबह तड़के ईडी की टीमें दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं। दिन निकलते ही दो जगहों पर एक साथ तलाशी शुरू हुई। पहली टीम सेंट्रल और साउथ कोलकाता के बीच स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम साल्ट लेक इलाके में I-PAC के पुराने दफ्तर में दाखिल हुई।

शुरूआत में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन करीब साढ़े ग्यारह बजे के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उसी घर पर पहुंच गईं, जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी।

ग्रीन फाइल और बड़े आरोप

ममता बनर्जी कुछ समय तक अंदर रहीं। बाहर निकलते वक्त उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी, जिसने सियासी हलकों में अटकलों को और तेज कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कराई जा रही है। उनका कहना था कि ईडी तृणमूल कांग्रेस की चुनावी

रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी से जुड़े संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही है।

I-PAC ऑफिस तक पहुंचा मामला

प्रतीक जैन के घर से निकलने के बाद ममता बनर्जी सीधे साल्ट लेक स्थित क-ढअउ के ऑफिस पहुंचीं। बताया गया कि वह पिछले दरवाजे से अंदर गईं। करीब 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी बाहर आते दिखे, जिनके हाथ में फाइलें थीं। इन फाइलों को उसी गाड़ी में रखा गया, जिससे मुख्यमंत्री वहां पहुंची थीं। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि ये दस्तावेज ईडी की तलाशी के दौरान बरामद हुए थे या नहीं।

सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा?

ममता बनर्जी ने तीखे शब्दों में कहा कि क्या ईडी और गृह मंत्री का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है। उन्होंने इसे घटिया राजनीति बताया और कहा कि उनकी पार्टी के दस्तावेज उठाकर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करें और अगर बीजेपी चुनावी लड़ाई जीतना चाहती है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़े।

बीजेपी का पलटवार

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जांच में दखल देने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डाली है और यह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क-ढअउ के दफ्तर में वोटर लिस्ट क्यों मिली और क्या वह कोई पार्टी कार्यालय है।

I-PAC क्या है और क्यों अहम?

एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जो राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच का काम करती है। इसकी शुरूआत 2013 में प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन ने की थी। बाद में इसका नाम बदलकर I-PAC रखा गया।

प्रशांत किशोर के सक्रिय राजनीति में आने के बाद संगठन की कमान पूरी तरह प्रतीक जैन के हाथों में आ गई। I-PAC 2021 से तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है और पार्टी के आईटी और मीडिया सेल की जिम्मेदारी भी संभालती है।

अब सबकी नजरें 09 जनवरी को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यह तय होगा कि ईडी की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और इस हाईवोल्टेज राजनीतिक टकराव का कानूनी अंजाम क्या होगा। एक बात तय है, I-PAC और ईडी की यह भिड़ंत बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक गूंजती रहेगी।

कौन हैं हाजी सलीम कुरैशी? शिंदे की शिवसेना के प्रत्याशी पर हुआ चाकू से जानलेवा हमला

(जीएनएस)।

मुंबई में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस सनसनीखेज घटना ने शहर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम बांद्रा के संत ज्ञानेश्वर नगर इलाके में प्रचार करते समय एक हमलावर ने उनके पेट में चाकू से वार किया। इस हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हाजी सलीम कुरैशी खतरे से बाहर हैं। अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

कौन हैं हाजी सलम कुरैशी?

हाजी सलीम कुरैशी बांद्रा के वार्ड नंबर 92 से शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के उम्मीदवार के रूप में बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि पहले वे एमआईएम से जुड़े थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदलकर शिंदे गुट का दामन थामा था। हाजी सलीम कुरैशी मुंबई के स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं और लंबे समय से जनता से जुड़े रहे हैं - स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान और सामाजिक कामों में भाग लेकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हो रहा खूनखराब

महाराष्ट्र में चुनावी हिंसा की यह अकेली घटना नहीं है।

शिवसेना नेता प्रमोद नाना भानगिरे ने बताया कि पुणे के श्रीराम चौक के पास चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर पथराव किया गया। इस दौरान शिवसेना उम्मीदवार सारिका पवार को भी निशाना बनाया गया था।

भानगिरे के अनुसार, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँचकर मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान कर रही है।

महाराष्ट्र AIMIM के प्रमुख इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजीनगर में अपनी पार्टी की रैली पर हमले का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, रैली की अनुमति थी और पुलिस भी मौजूद थी, फिर भी 20-25 हथियारबंद लोगों ने समर्थकों और वाहनों पर हमला किया।

इस हमले में कई समर्थक घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुँचा। जलील ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत शांतिपूर्ण चुनाव लड़ रही है और ऐसी हिंसा या धमकियों से वे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि यह उन्हें और मजबूत करेगी।

15 जनवरी को होगा मतदान

बता दें, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ सहित राज्य की 29 नगर निगमों में चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी।

अपाचे हेलीकॉप्टर, पीएम मोदी पर झूठ, ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देता भारत, 'कोई मतलब नहीं'

अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बोले गए झुठ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन, फिर भी भारत उनकी मिट्टी पलीद करने से संयम बरत रहा है तो इसके पीछे खास वजह है।

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो हालिया दावा किया है, फैक्ट चेक में वह पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। फिर भी भारत उन्हें झूठा साबित करने में संयम बरत रहा है। दरअसल, भारत इसका जवाब इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि यह ट्रंप की तरह तू-तू, मैं-मैं वाली स्थिति नहीं आने देना चाहता। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील करीब-करीब अंतिम चरण में है और इसे पटरी से उतारना कूटनीतिक परिपक्वता नहीं माना जा रहा।

ट्रंप के बयानों पर बरत रहा संयम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था, 'पीएम मोदी मुझसे खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत को ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है।' 'प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे, सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज। हां।' पीएम मोदी को फ्रेंड कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से उनके लिए इस तरह का टोन पहली बार देखने को मिला है। शायद रूस के साथ भारत के रिश्तों को पचाने के लिए वे कतई तैयार नहीं हैं। लेकिन, फिर भी भारत ने अबतक ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देने में संयम ही बरता है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली डिप्लोमेटिक सर्किल का मानना है कि ट्रंप के भड़काऊ बयानों पर संयम बरतना और राजनीतिक परिपक्वता दिखाना ही उचित है। सूत्रों के अनुसार 'जैसे को तैसा' वाली प्रतिक्रिया का 'प्रतिकूल' असर पड़ सकता है। जब दोनों देश ट्रेड डील को फाइनल करने के प्रयास में हैं,'पॉइंट स्कोर करने का कोई मतलब नहीं है।'

'हर टिप्पणी पर कमेंटरी जरूरी नहीं'

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप की हर टिप्पणी पर एक-एक कर कमेंटरी करते जाने की जरूरत नहीं है, व्यापार वार्ता पर फोकस करना भारत की प्राथमिकता है। दिसंबर में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि ज्यादातर मामले सुलझा लिए गए हैं और मार्च तक भारत-अमेरिका में समझौता हो जाने की संभावना है।

फैक्ट-चेकिंग में ट्रंप के दावे निकले झूठे

डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन कई तरह से उनकी छानबीन से पता चलता है कि उन्होंने काफी बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, जिसमें देरी होने पर पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। लेकिन, सारे तथ्य यह साबित करते हैं कि भारत ने सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर ही मंगवाए थे और उनकी डिलवरी भी दिसंबर, 2025 में पूरी हो चुकी है।

युद्ध रुकवाने के भी करते रहे हैं दावे

इससे पहले ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के अनेकों दावे कर चुके हैं, जिसे भारत बार-बार खारिज कर चुका है। ट्रंप युद्ध रुकवाने के ऐसे दावे अन्य देशों के लिए भी करते आए हैं और उनके युद्ध रोकने दावों की संख्या बढ़कर अब 8 हो चुके हैं। इस आधार पर वह अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मांग चुके हैं और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा तो वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बेडरूम से आधी रात में अमेरिकी मिलिट्री भेजकर उठवा लिया।

आकिब नबी ने 9वें नंबर पर आकर जड़ा शतक, टीम को दिलाई जीत

(जीएनएस)।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अंतिम ग्रुप मैच में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिला। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने हैदराबाद के जबड़े से जीत छीन ली। इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे आकिब नबी, जिन्हें हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है।

हार हुई बाजी जीत गई टीम

हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 268 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जम्मू-कश्मीर की शुरूआत किसी दुःस्वप्न जैसी रही। हैदराबाद के कप्तान सी.वी. मिलिंद और स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों के सामने जेके का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर

गया। एक समय टीम का स्कोर 90 रन पर 7 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि मैच अगले कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा।

9वें नंबर पर आकर जड़ा शतक

जब हार निश्चित लग रही थी, तब नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए आकिब नबी ने मैदान पर कदम रखा। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। आकिब ने अपने लिस्ट-ए करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने महज 82 गेंदों में नाबाद 114 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आकिब ने अपना शतक केवल 65 गेंदों में पूरा किया।

आकिब का साथ दिया वंशज शर्मा (नाबाद 69 रन) ने। इन दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 182 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जो विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी 8वें विकेट की पार्टनरशिप है। इस करिश्माई बल्लेबाजी की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने 13 गेंद शेष रहते ही 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया।

लखनऊः राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बच्चों के लिए किड्स जोन बनेगा, एलडीए ने 2 एकड़ भूमि पर विकास को मंजूरी दी

लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रस्तावित किड्स जोन विकास

लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रस्तावित किड्स जोन विकास

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों, खासकर बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल (गोमती नगर विस्तार) में 2 एकड़ भूमि पर आधुनिक किड्स जोन विकसित किया जाएगा। छ्ळ्ऊ की संचालन समिति की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह किड्स जोन बच्चों के मनोरंजन, शिक्षा और शारीरिक विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के शहर विकास और परिवार कल्याण के प्रयासों से लखनऊ में नई सुविधाएं जुड़ रही हैं, जो जनता, खासकर बच्चों और परिवारों के लिए बड़ा लाभ होगा।

प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएंः बच्चों का सपनों का जोन

छ्ळ्ऊ की बोर्ड बैठक में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। 2 एकड़ क्षेत्र में किड्स जोन बनाने का निर्णय लिया गया, जो बच्चों के लिए सुरक्षित और आकर्षक होगा। यह जोन खेलकूद, शिक्षा और मनोरंजन का केंद्र बनेगा। छ्ळ्ऊ अधिकारियों के अनुसार, यहां आधुनिक प्लेग्राउंड, एडवेंचर जोन, वॉटर पार्क जैसी सुविधाएं और इंटरएक्टिव लर्निंग एरिया विकसित किए जाएंगे।

यह पहल शहर के परिवारों को क्वालिटी टाइम बिताने का नया स्थान देगी। गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में यह जोन लखनऊ की खूबसूरती बढ़ाएगा और पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का विकासः बड़ा प्लान

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहले से ही लखनऊ का प्रमुख आकर्षण है। छ्ळ्ऊ यहां व्यापक विकास कर रहा है, जिसमें किड्स जोन नया अध्याय होगा। बोर्ड बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, लेकिन किड्स जोन को प्राथमिकता दी गई। छ्ळ्ऊ उपाध्यक्ष और अधिकारी इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सरकार के प्रयासः परिवार और बच्चों का विकास

योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में पार्क, खेल मैदान और परिवार केंद्रित सुविधाएं बढ़ा रही है। छ्ळ्ऊ के इस कदम से लखनऊ में बच्चों के लिए सुरक्षित और मजेदार जगहें बढ़ेंगी। मिशन शक्ति और अन्य अभियानों की तरह यह पहल भी जनता के हित में है। बच्चों का शारीरिक-मानसिक विकास और परिवारों का मनोरंजन सुनिश्चित होगा।

प्रमुख बिंदु एक नजर में

विवरण जानकारी

स्थान राष्ट्र प्रेरणा स्थल, गोमती नगर विस्तार

क्षेत्रफल 2 एकड़

विकास एजेंसी ल ा ख न ा ऊ विकास प्राधिकरण (छ्ळ्ऊ)

मुख्य सुविधाएं प्ले ग्र ा उ ंड, एडवेंचर जोन, लर्निंग एरिया

मंजूरी संचालन समिति बोर्ड बैठक

लाभ बच्चों का विकास, परिवार मनोरंजन

यह तालिका प्रोजेक्ट के मुख्य पहलुओं को स्पष्ट करती है।

निष्कर्षः बच्चों के लिए नई खुशी की किरण

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किड्स जोन का विकास लखनऊ के परिवारों के लिए बड़ा तोहफा है। छ्ळ्ऊ के प्रयासों से शहर में नई सुविधाएं जुड़ रही हैं, जो जनता के हित में हैं। यह जोन बच्चों को खेलने, सीखने और खुश रहने का स्थान देगा। सरकार की नीतियों से लखनऊ और आधुनिक और परिवार अनुकूल बन रहा है। जल्द शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट से शहर की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा।

रकाबगंज चौराहा अंधेरे में डूबाः राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, व्यापारियों में आक्रोश - मंडल ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी

लखनऊ रकाबगंज चौराहा अंधेरे में तिरंगा अपमान व्यापारी शिकायत

रकाबगंज चौराहे पर अंधेरा और तिरंगे की स्थिति

लखनऊ,

लखनऊ के व्यस्त रकाबगंज चौराहे पर नगर निगम द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) अंधेरे में लहरा रहा है, जिसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। चौराहा महीनों से अंधेरे में डूबा है, जिससे व्यापारियों और राहगीरों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रकाबगंज व्यापार मंडल ने मेयर और पुलिस कमिश्नर को लिखित पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मंडल ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। यह मामला शहर की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा है, जो प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमानः अंधेरे में लहराता तिरंगा

नगर निगम द्वारा चौराहे पर लगाया गया तिरंगा रात में अंधेरे में लहरा रहा है, जो ध्वज संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। व्यापार मंडल का कहना है कि लाखों लोग और वाहन इस चौराहे से गुजरते हैं। अंधेरा होने से व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में है और कोई घटना हो सकती है। मंडल ने पूछा - इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि राष्ट्रीय ध्वज पर ध्यान नहीं, तो क्षेत्र की लाइटिंग का क्या हाल होगा?

व्यापार मंडल ने मेयर और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडल ने चेतावनी दी कि मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा।

व्यापारियों का आक्रोशः सुरक्षा और सम्मान पर सवाल

रकाबगंज व्यापार मंडल ने कहा कि चौराहा व्यस्त होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। अंधेरे में चोरी, लूट या दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी असहनीय है। मंडल ने नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वे 'कान में रुई डालकर' बैठे हैं।

सरकार के प्रयासः शहर विकास और सुरक्षा पर फोकस

लखनऊ नगर निगम और प्रशासन शहर की लाइटिंग और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अभियान चला रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। लेकिन इस चौराहे की समस्या महीनों से लंबित है। व्यापार मंडल की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है।

त्वरित समाधान की जरूरत

रकाबगंज चौराहे की यह समस्या राष्ट्रीय सम्मान और जनसुरक्षा से जुड़ी है। व्यापार मंडल का आक्रोश जायज है। नगर निगम और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए - लाइटिंग बहाल करें और ध्वज को उचित रोशनी दें। यह जनता के हित में होगा और शहर की छवि सुधरेगी। उम्मीद है शिकायत का जल्द समाधान होगा।

अप्रेंटिसशिप योजना से 2025-26 में अब तक 83 हजार से अधिक युवाओं को मिला उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर

एमएसएमई और बड़े उद्योगों में शिक्षुता को बढ़ावा, योगी सरकार दे रही है प्रतिपूर्ति का लाभ

नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनाओं के तहत युवाओं व अधिष्ठानों को मिल रहा सीधे लाभ

पिछले 4 वर्षों में 795 नए अधिष्ठान पोर्टल पर पंजीकृत, प्रशिक्षण अवसरों में बड़ा विस्तार

सीएमएपीएस योजना से 6,164 नए अभ्यर्थी लाभान्वित, रोजगारपरक प्रशिक्षण को मिल रही रफ्तार

बीते पौने 9 वर्षों में 4 लाख से अधिक प्रशिक्षु युवाओं को औद्योगिक संस्थानों में मिला अवसर

लखनऊ, 8 जनवरी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण को नई रफ्तार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में मजबूत पहल की है। राज्य में संचालित अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें। वर्ष 2025-26 में अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 83,277 युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है। इससे युवाओं को उत्पादन इकाइयों, सेवा क्षेत्र और लघु-मध्यम उद्योगों में काम सीखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा 'सीखते हुए कमाएं' और उद्योगों के अनुरूप कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें।

सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, व्यावहारिक अनुभव भी मिल रहा

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलतो राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का हब बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्रेंटिसशिप योजना के माध्यम से युवाओं को सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि काम का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। हमारे लिए लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनाओं के तहत दी जा रही प्रतिपूर्ति से अधिष्ठानों की रुचि बढ़ी है और इससे रोजगारपरक अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्य सरकार हर युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप कौशल और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपलब्ध कराई जा रही प्रतिपूर्ति की सुविधा

उत्तर प्रदेश में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संबंधित अधिष्ठानों और अभ्यर्थियों को प्रतिपूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग मिलता है, वहीं अधिष्ठानों को भी प्रशिक्षुओं को रखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। योगी सरकार का मानना है कि यह मॉडल युवाओं और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी है।

अप्रेंटिसशिप के दायरे को बढ़ाने के लिए सशक्त संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। इसी के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 795 नवीन अधिष्ठानों को पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया है। नए पंजीकरण से विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण के अवसरों का दायरा बढ़ा है और स्थानीय स्तर पर युवाओं को उद्योगों तक पहुंच आसान हुई है। इसके साथ ही सीएमएपीएस योजनान्तर्गत 6,164 नए अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। विभाग के अनुसार, इन योजनाओं के जरिए युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगारपरक कौशल और औद्योगिक अनुभव भी मिल रहा है, जिससे नियुक्ति की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

विभागीय स्तर पर प्रक्रियाओं को बनाया गया सरल

राज्य में कौशल विकास की इस सतत प्रक्रिया का बड़ा परिणाम यह रहा कि बीते लगभग नौ वर्षों में 4 लाख से अधिक प्रशिक्षु युवाओं को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में सेवायोजित कराया गया है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अप्रेंटिसशिप को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हुए युवाओं को उद्योगों, स्टार्टअप्स और टरटए सेक्टर से जोड़ा जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है और उद्योगों के साथ समन्वय भी बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि कौशलयुक्त युवा न केवल अपने लिए अवसर पैदा करेंगे, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश माहौल को भी मजबूती देंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यालय में शासकीय कार्यों का निस्तारण

आज दिनांक 08/01/2026 दिन वृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित-उ०प्र०अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यालय में शासकीय कार्यों का निस्तारण किया तथा विभिन्न जनपदों से आए पीड़ितों व कार्यकताओं से भेंट कर उनकी समस्याएं सुना और शीघ्र निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

आज भेंट वालों में श्री रमेश चंद्र कुण्डे जी सदस्य,श्रीमती अनीता गौतम जी सदस्य,श्री राम लखन रावत प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा कानपुर,श्रीमती गरिमा सिंह भदौरिया प्रधान काकराबाद लखनऊ,श्री राजू पासी तथा श्री विनोद रावत प्रधान,श्री सुरेन्द्र कुमार रावत मिल्कीपुर अयोध्या,डीडीसी शहंशाह जी,एडवोकेट सुजा वारशी जी,श्री रज्जाक अली जी बाराबंकी,झांसी से श्री जितेन्द्र धानुक जिला उपाध्यक्ष तथा नीतू महामंत्री महिला मोर्चा, सहित अन्य काफी लोगों से मुलाकात

लखनऊः ऋक्फ़ड्राफ्ट सूची पर सीएम योगी की सख्ती, मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश - पात्र-अपात्र की पड़ताल और G RAM G योजना का प्रचार

सीएम योगी SIR ड्राफ्ट सूची पर मंत्रिमंडल को निर्देश बैठक

यूपी SIR ड्राफ्ट सूची पर सीएम योगी की सख्तीः मंत्रिमंडल को पड़ताल और G RAM G प्रचार की जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल को सक्रिय कर दिया है। मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने निर्देश दिए कि सूची में पात्र मतदाताओं के नाम न होने की पड़ताल करें, अपात्र नामों की जांच करें और जनता को सिपाही भर्ती के फैसले की जानकारी दें। साथ ही विकसित भारत ऋफ्अट ऋयोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। यह अभियान जनता के हित में है, जो मतदाता सूची को शुद्ध बनाकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा। योगी सरकार की यह पहल लोकतंत्र और जनकल्याण की मजबूती का प्रमाण है।

ऋक्फ़ड्राफ्ट सूची पर सख्त निर्देशः पात्र-अपात्र की पड़ताल

ऋक्फ़ड्राफ्ट सूची में बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा - 'सूची में कितने पात्र लोग छूट गए हैं, इसकी पड़ताल करें। अपात्र लोगों के नाम भी जांचें।' मंत्रियों को प्रभार जिलों में जाकर ग्रामीणों से संवाद करने और दावा-आपत्ति प्रक्रिया में सहायता करने के निर्देश दिए गए। यह कदम सूची को और शुद्ध बनाएगा, जिससे हर पात्र मतदाता का नाम जुड़ेगा और फर्जी वोटिंग रुकेगी।

सिपाही भर्ती और ऋ फ्अट ऋ योजनाः जनता को जानकारी दें

सीएम ने मंत्रियों को सिपाही भर्ती के हालिया फैसले जनता तक पहुंचाने को कहा। साथ ही विकसित भारत ऋ फ्अट ऋयोजना का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं और अन्य कार्यक्रमों से योजना के लाभ बताएं।

यूपी में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार ट्रक ने टैम्पो को मारी जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत...6 घायल

(जीएनएस)।

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी...

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन महिलाओं समेत छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना बुधवार रात को हुई जब ये लोग मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना कस्बे की ओर टैम्पो में लौट रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) गजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान गुलशन (40) और आशिफा (10) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

फरार चालक की तलाश जारी

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। हादसे का सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद

शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है।

यूपी के 8.74 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर संकट! 31 जनवरी तक यह काम नहीं किया तो फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। अगर उन्होंने तय समयसीमा के भीतर एक जरूरी औपचारिकता पूरी नहीं की, तो फरवरी में मिलने वाली उनकी सैलरी रुक सकती है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि......

छ्ष्र्ू ल्लङ्घ६ ठी६२ः उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। अगर उन्होंने तय समयसीमा के भीतर एक जरूरी औपचारिकता पूरी नहीं की, तो फरवरी में मिलने वाली उनकी सैलरी रुक सकती है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। दरअसल, यूपी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है। शासनादेश में साफ लिखा है कि

जो कर्मचारी इस तारीख तक अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन फरवरी में नहीं दिया जाएगा।

मुख्य सचिव के आदेश से विभागों में हलचल

यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से जारी किया गया है। इसके बाद से सभी सरकारी विभागों में हलचल मच गई है। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से समय पर संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। इसे सिर्फ औपचारिक आदेश नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

8.74 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा नियम

शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत लागू की गई है। इस नियम के मुताबिक हर सरकारी कर्मचारी को हर साल अपनी अर्जित चल और अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देना जरूरी है। अब इस पूरी प्रक्रिया को मानव संपदा पोर्टल से जोड़ दिया गया है, ताकि संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे और पारदर्शिता बनी रहे। प्रदेश में इस समय करीब 8.74 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मचारी, सचिवालय और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

कौन-कौन सी जानकारी देनी होगीए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। इसमें शामिल हैं—

- जमीन और मकान - फ्लैट - वाहन
- बैंक जमा
- बीमा
- शेयर और अन्य निवेश

और ये भी पढ़े

लंगूर की आवाज निकालकर ले जाओ नौकरी! मोटी सैलरी के साथ मिलेगा जीवन बीमा...सरकार ने निकली अनोखी...

लंगूर की आवाज निकालकर ले जाओ नौकरी! मोटी सैलरी के साथ मिलेगा जीवन बीमा...सरकार ने निकली अनोखी...

यूपी में ठंड का कहर बरकरार! 31 दिसंबर को शीतलहर और घना कोहरा, नए साल पर इन 14 जिलों में बारिश का...

नोडल अधिकारी और ऊ्ळ्ड की बढ़ी जिम्मेदारी

इस आदेश के बाद नोडल अधिकारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। शासन ने कहा है कि—

नोडल अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल की समीक्षा करेंगे। ऊ्ळ्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन कर्मचारियों का विवरण अपलोड नहीं है, उनका वेतन रोका जाए। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि इस बार किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पहले कई बार समयसीमा बढ़ा दी जाती थी, लेकिन इस बार वेतन से सीधा जुड़ाव कर सख्ती दिखाई जा रही है।

कर्मचारी संगठनों ने जताई परेशानी

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों को तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में तैनात कर्मचारियों को। हालांकि शासन का दावा है कि मानव संपदा पोर्टल को पहले से ज्यादा आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।जरूरत पड़ने पर विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की मदद के निर्देश भी दिए गए हैं।

कैसे भरें संपत्ति विवरण

अधिकारियों के मुताबिक—

- मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें
- 'संपत्ति विवरण' सेक्शन में जाएं
- जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करें
- सबमिट करने के बाद उसकी पावती या रसीद सुरक्षित रखें
- समय रहते प्रक्रिया पूरी करने वाले कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है।

लखनऊ पुलिस का सड़क पर 'एक्शन', अवैध अतिक्रमण और ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां तो हुआ भारी चालान

ऊ्ळ्ढ ट्रैफिक कमलेश दीक्षित के निर्देशन में निशातगंज, कैसरबाग, अशोक लाट और लालबाग चौराहे पर चला विशेष प्रवर्तन अभियान।

फुटपाथ पर अवैध दुकानें, सड़क किनारे लगे ठेले और खोमचे वालों को हटाकर यातायात मार्ग कराया गया सुगम।ꟹ

दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के सामने वाहन न खड़े करने और पार्किंग नियमों का पालन करने की दी गई कड़ी चेतावनी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा चला; एक ही दिन में कुल 4048 चालान किए गए।

ꟹ:ꟹ

बिना हेलमेटः 1390

नो-पार्किंग उल्लंघनः 1838

गलत दिशा से चल रहे लोगो का : 453

सीज किए गए वाहनः 87

मरीजों के इलाज में न हो लापरवाही, योगी सरकार आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में कर रही भुगतान

लखनऊ, 8 जनवरीः योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले परिवारों के लिए जहां कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया गया है, वहीं योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक वर्ष में आयुष्मान योजना के क्लेम निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नए क्लेम के साथ पुराने लंबित मामलों का भी तेजी से किया जा रहा निस्तारण

स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज(साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जनवरी-25 में जहां क्लेम की पेंडेंसी 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर-25 तक यह घटकर मात्र 3 लाख रह गयी है। इसे भी जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत प्रति माह औसतन 2 लाख से अधिक क्लेम अस्पतालों से प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले क्लेम का समयबद्ध निस्तारण एक बड़ी चुनौती है।